साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 45 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 26 जून 2024 से 2 जुलाई 2024 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

स्वच्छ भारत मिशन मध्यप्रदेश डायरेक्टर ने नगर निगम सहित अन्य नगरीय निकायों द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली

स्वच्छता के प्रति व्यापक पैमाने पर जागरूकता तथा जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु दिए आवश्यक निर्देश

सागर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में अच्छी रैंकिंग लाने के लिए सागर नगर निगम सहित जिले के सभी नगरीय निकायों द्वारा प्रारंभिक तैयारियां प्रारंभ की जा चुकी हैं। सागर नगर निगम सहित जिले के निकायों द्वारा की जा रही प्रारंभिक तैयारियों के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करने हेतु शनिवार को नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल से मिशन डायरेक्टर श्री अक्षय त्रेमवाल स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) ने सागर में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने समीक्षा बैठक में सागर जिले में स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु किये जा रहे कार्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण के निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार तैयारियों को गति देने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देश दिए।

सागर स्मार्ट सिटी के सभा कक्ष में आयोजित नगर निगम और जिले के समस्त नगरीय निकायों की बैठक में मुख्य रूप से नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री के साथ जिले की समस्त निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के डायरेक्टर श्री अक्षय त्रेमवाल ने निकायों द्वारा की जा रही स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सीपीटी की जो भी राशि निकायों के पास शेष है वह उन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करें,इसके अलावा उन्होंने समस्त निकायों के सीएमओ से कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में आप सबको अच्छा प्रदर्शन करना है और रैंकिंग को बढ़ाना है । उन्होंने शासन की महत्वपूर्ण योजना नमस्ते योजना को व्यापक तौर पर चलने और इसका प्रचार-प्रसार करने के लिए समस्त सीएमओ को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नमस्ते योजना के अंतर्गत निकायों को सेप्टिक टैंक की सफाई वाहन के साथ मशीन से कराना है अगर यह संभव नहीं है और अगर सेप्टिक टेंक की सफाई बिना मशीन की मदद से सफाई मित्र करता है तो उसके स्वास्थ्य और जान- माल की रक्षा के लिए समस्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाएं क्योंकि बिना सेफ्टी उपकरण के सेप्टिक टैंक में उतर कर सफाई करने से सफाई मित्रों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना हो सकता है। सावधानी के साथ सेफ्टी टैंक की सफाई की जाए इस पर विशेष ध्यान देना है।

बैठक में उन्होंने नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए की जा रही तैयारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा कई नवाचार और जागरूकता के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहे हैं जो सराहनीय हैं परंतु इन प्रयासों को व्यापक पैमाने पर करने के लिए लोगों में जागरूकता और जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री ने बैठक में बताया कि नगर निगम द्वारा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु कई कार्य एवं नवाचार किये जा रहे हैं । पॉलिथीन के उपयोग को रोकने के लिए लोगों को पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है साथ ही कांच के गिलास या मिट्टी के कप देकर प्रोत्साहित भी किया जा रहा है । इसके अलावा नगर निगम द्वारा सागर का सुकून और कचरा खुद बोलता है मैं किस घर का हूं ये दो अभियान भी चलाए जा रहे हैं जिसमें एक अभियान के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है वहीं दूसरे अभियान के माध्यम से शहर में गंदगी फैलाने वाले और कचरा फेंकने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की जा रही है । सागर स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कैमरों की मदद से कचरा फेकने वालों की वीडियो फुटेज निकालकर पहचान की जाती है इसके आधार पर चालानी कार्यवाही होती है।

बैठक के पश्चात मिशन डायरेक्ट श्री अक्षय त्रेमवाल निगमायुक्त श्री राजकुमार खत्री के साथ मसवासी ग्रंट स्थित कचरा प्रसंस्करण प्लांट का स्थल निरीक्षण करने पहुँचे। इस दौरान उन्होंने प्लांट पर पहुंचने वाले गीले सूखे कचरे से बनने वाली खाद और इस प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले आरडीएफ के उपयोग की जानकारी ली और प्लांट संचालक को निर्देश दिये की आरडीएफ को फैक्ट्री या विद्युत प्लांट में भेजा जाये। इससे आरडीएफ का डंप साइड पर एकत्रिकरण नहीं होगा,इस आरडीएफ का बड़े-बड़े प्लांटों में इधन के रूप में उपयोग किया जाता है। उन्होंने मसवासी कचरा प्रसंसकरण प्लांट में बनी लेबोरेटरी का भी निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिले लोकतंत्र सेनानी संघ के पदाधिकारी

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आज मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। प्रतिनिधि मंडल द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव को आगामी 26 जून को संघ द्वारा आपातकाल की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम का निमंत्रण दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में श्री तपन भौमिक, श्री सुरेंद्र द्विवेदी और अन्य पदाधिकारी शामिल थे।

उत्तर प्रदेश में है बायोगैस उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक, लेकिन चुनौतियां कम नहीं

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश में कंप्रेसड (संपीड़ित) बायोगैस यानी सीबीजी उत्पन्न करने की क्षमता देश में सबसे अधिक है, इसलिए उत्तर प्रदेश को इसके उपयोग की दिशा में तेजी से काम करना चाहिए। देश की प्रमुख थिंक टैंक संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेला उत्तरप्रदेश में देश की कुल क्षमता का 24 प्रतिशत सीबीजी का उत्पादन हो सकता है। वो भी खासकर पश्चिमी जिले मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर और अलीगढ़ में यह क्षमता सबसे अधिक है। सीएसई ने अपनी यह रिपोर्ट मुजफ्फरनगर में आयोजित एक संगोष्ठी में जारी की। संगोष्ठी का आयोजन सीएसई और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

उल्लेखनीय है कि सीबीजी विभिन्न तरह के कचरों या व्यर्थ चीजों जैसे कबाड़ आदि से बनाई जाती है, जिसमें नगरपालिका का ठोस अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, प्रेस-मड और पशु अपशिष्ट शामिल हैं। यह बायोगैस का शुद्ध संस्करण है, और इसे बायो-सीएनजी भी कहा जाता है। सीबीजी का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा मीथेन गैस होती है और यह जैविक अपशिष्ट या बायोमास से अवायवीय पाचन के माध्यम से बनती है। संगोष्ठी में सीएसई के औद्योगिक प्रदूषण कार्यक्रम निदेशक निवित कुमार यादव ने कहा- भारतीय राज्यों में, उत्तर प्रदेश ने अपनी महत्वाकांक्षी जैव ऊर्जा नीति के साथ इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। सीबीजी के लिए 750 करोड़ रुपये (2022-27) आवंटित किए जाने के अलावा सब्सिडी, पट्टे के लिए भूमि और अन्य प्रोत्साहन भी प्रदान किए गए हैं। इस संगोष्ठी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सीबीजी उत्पादकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने, सफल प्रथाओं को साझा करने, स्टार्ट-अप के अवसरों को प्रचारित करने, जिला स्तरीय जैव ऊर्जा समितियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और किसान-उत्पादक समितियों को जैव ऊर्जा की क्षमता के बारे में शिक्षित करना है। इस क्षेत्र में राज्य सरकार की प्रगति पर यादव की बातों को दोहराते हुए, यूपीनेडा के सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी पंकज सिंह ने कहा- उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे उन्नत जैव ऊर्जा नीति है और आगामी सीबीजी परियोजनाओं की संख्या में यह सबसे आगे है। यहां 128 सीबीजी परियोजनाओं में से 15 चालू हैं, जबकि शेष 113 निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

उप-उत्पादों/बायोस्लरी/ जैविक खाद (एफओएम) का सीमित उठान- सीबीजी प्लांट बायोस्लरी उत्पन्न करते हैं, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। हालांकि, सीबीजी प्लांट द्वारा उत्पादित बायोस्लरी के लिए कोई खरीदार नहीं हैं। सी एस ई के अक्षय ऊर्जा के उप कार्यक्रम प्रबंधक और सीबीजी पर सीएसई की रिपोर्ट के लेखक डॉ राहुल जैन कहते हैं- राजस्व का संभावित स्रोत माने जाने के बजाय, बायोस्लरी को अपशिष्ट के रूप में देखा जाता है। प्लांट मालिक या तो इसे आस-पास के किसानों को मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं या खाली जमीन पर इसका निपटान कर रहे हैं। बायोस्लरी की विशेषताओं, उपयुक्त अनुप्रयोग विधियों और संभावित लाभों के बारे में जागरूकता की कमी है। तेल और गैस विपणन कंपनियों द्वारा आंशिक गैस उठाव- ये कंपनियाँ बाज़ार की मांग के आधार पर सीबीजी संयंत्रों से 'सर्वोत्तम प्रयास' के आधार पर गैस प्राप्त करती हैं। इससे संयंत्र मालिक अपने पूरे गैस उत्पादन को नहीं बेच पाते हैं। कुछ संयंत्र अपनी क्षमता से कम पर केवल इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि वे अपनी पूरी गैस नहीं बेच पाते। संयंत्रों के पास सीएनजी गैस पाइपलाइनों का न होना इस दिशा में एक और चुनौती है। यह देखा गया है कि 5 टन प्रति दिन (टीपीडी) से कम क्षमता वाले प्लांट के लिए कैस्केड के माध्यम से गैस परिवहन एक व्यवहार्य विकल्प है; इस सीमा से ऊपर की किसी भी चीज़ के लिए, सबसे प्रभावी ऑफटेक मॉडल गैस पाइपलाइनों के माध्यम से है। कुशल तकनीकी मानव बल की कमी- इन संयंत्रों को अक्सर परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप गैस रिसाव, अकुशलता और क्षमता से कम उत्पादन जैसी समस्याएँ होती हैं। इस समस्या का कारण बायोगैस उत्पादन प्रणालियों और संयंत्र संचालन की पर्याप्त समझ रखने वाले कामगारों की अनुपस्थिति है। वित्तपोषण संबंधी मुद्दे- बैंक शायद ही कभी सीबीजी परियोजनाओं के वित्तपोषण में कोई रुचि दिखाते हैं - उनकी चिंताएं जोखिम, कम मार्जिन और उद्योग की गैर-मानकीकृत प्रकृति के इर्द-गिर्द घूमती हैं। बैंकों को आम तौर पर उच्च संपार्श्विक की आवश्यकता होती है, और ब्याज दरें न्यूनतम 11.5 प्रतिशत से शुरू होती हैं। इसके अलावा, ऋण देने वाले संस्थानों में सीबीजी प्रस्तावों का मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा आती है। जैन ने बताया कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तरफ उचित योजना के अभाव के कारण, ज़्यादातर सीबीजी संयंत्र अपनी वास्तविक डिजाइन की गई क्षमता से कम पर चल रहे हैं। अपस्ट्रीम दिशा में, संयंत्र को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में फीडस्टॉक नहीं मिल पा रहा है। संयंत्र में सालाना ज़रूरत से ज़्यादा फीडस्टॉक की उपलब्धता के लिए योजना बनाये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए संयंत्र संचालकों को फीडस्टॉक प्राप्त करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं (किसानों, गन्ना मिल मालिकों और शहर की नगर पालिकाओं) के साथ मिलकर काम करना होगा। डाउनस्ट्रीम दिशा में, सीबीजी संयंत्र के पास सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर की गैर मौजूदगी के कारण गैस की बिक्री एक बड़ी चुनौती है। संयंत्रों को या तो सीएनजी गैस ग्रिड के पास या फिर जहां औद्योगिक या परिवहन अनुप्रयोगों के लिए सीएनजी की उच्च मांग है, वहां स्थापित करना महत्वपूर्ण है। किसानों को शेयरधारकों के रूप में शामिल करें- जागरूकता अभियानों के माध्यम से किसान-उत्पादक संगठनों को तीसरे पक्ष की निजी संस्थाओं की जगह फीडस्टॉक एग्रीगेटर की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे परियोजना में साझेदारों के रूप में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी , जिससे जैव ऊर्जा परियोजनाओं में समग्र लाभ साझाकरण को बढ़ावा मिलता है। गैस विपणन कंपनियों द्वारा पूर्ण गैस उठाव सुनिश्चित करें- इसे सुनिश्चित करने के लिए, सीबीजी संयंत्रों के पास गैस पाइपलाइन बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए एक रणनीतिक योजना तैयार करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग को बढ़ावा देने के लिए, ट्रैक्टरों और दोपहिया वाहनों को सीएनजी पर चलाने के लिए प्रोत्साहन देना या सीएनजी से चलने वाली कृषि मशीनरी को अपनाने की दिशा में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। किसानों को बायोस्लरी/एफओएम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित/संवेदनशील बनाएं- किसानों को कार्बन-समृद्ध एफओएम के उपयोग के संभावित लाभों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। एफओएम के उपयोग हेतु किसानों के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रमों को संस्थागत बनाने की संभावना का पता लगाया जा सकता है। एफओएम के सकारात्मक प्रभावों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) शिक्षा और आउटरीच प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

धीमी पड़ रही है पृथ्वी के आंतरिक कोर के घूमने की रफ्तार, जानिए किन चीजों पर पड़ेगा असर

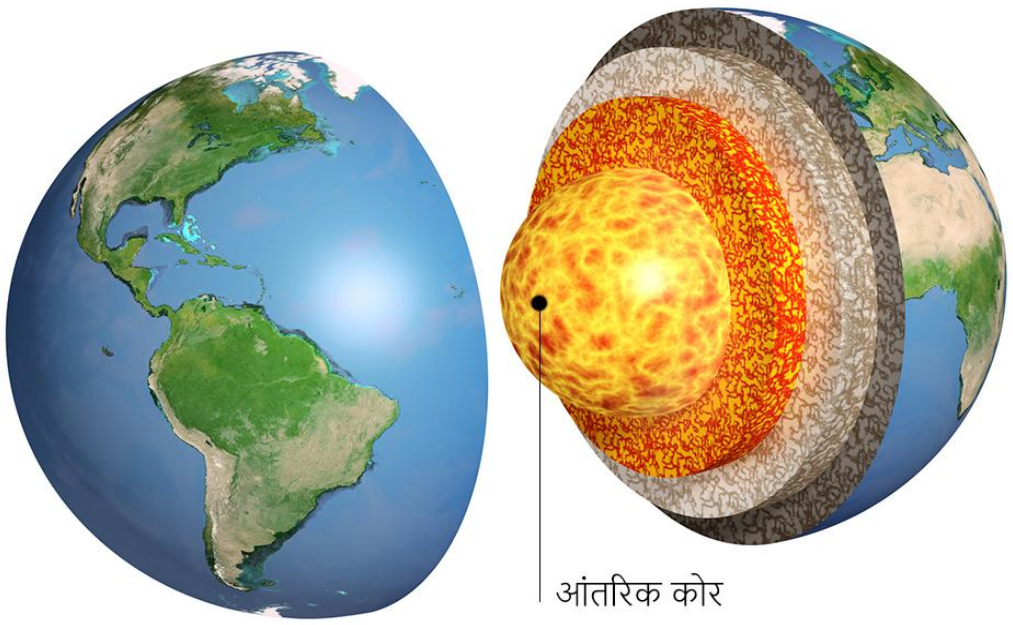

मुंबई। एक नई रिसर्च से पता चला है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर के घूमने की रफ्तार उसकी सतह की तुलना में धीमी पड़ रही है। रिसर्च में इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिले है कि आंतरिक कोर की रफ्तार 2010 के आसपास कम होनी शुरू हो गई थी। ऐसे में आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आंतरिक कोर के घूमने की रफ्तार में होने वाला बदलाव इंसानों को कैसे प्रभावित करेगा। बता दें कि वैज्ञानिकों ने अंदेशा जताया है कि इसकी वजह से आने वाले समय में दिन की अवधि पर असर पड़ सकता है। हालांकि साथ ही उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि दिन के समय पर पड़ने वाला यह प्रभाव एक सेकंड से भी कम होगा। मतलब साफ है यह बदलाव आम लोगों द्वारा महसूस नहीं किया जाएगा। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए इस अध्ययन के नतीजे 12 जून 2024 को जर्नल नेचर में प्रकाशित हुए हैं।

पृथ्वी की संरचना में नजर डालें तो यह मुख्य रूप से तीन परतों में बनी है, जिसकी सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी का यह वो हिस्सा है जिसपर हम इंसान और जैवविविधता बसती है। इसके बाद मेंटल है और तीसरी एवं सबसे अंदरूनी परत को कोर कहा जाता है। यह कोर दो हिस्सों आंतरिक और बाह्य में बंटा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक पृथ्वी का यह आंतरिक कोर लोहे और निकल से बना एक ठोस गोला है, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपने स्थान पर स्थिर बना रहता है। यदि इसके आकार की बात करें तो यह करीब-करीब चंद्रमा के बराबर है। इसकी गहराई के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पृथ्वी की ऊपरी सतह से करीब 4,828 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे स्थित है। चूंकि इतनी गहराई में होने की वजह से सीधे तौर पर इसे देखा या उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। ऐसे में वैज्ञानिक इसके अध्ययन के लिए भूकंपीय तरंगों की मदद लेते हैं। देखा जाए तो वैज्ञानिकों के बीच इस आंतरिक कोर की गति को लेकर पिछले दो दशकों से बहस चल रही है। कुछ शोधों का मानना है कि यह आंतरिक कोर पृथ्वी की सतह से भी ज्यादा तेजी से घूमता है। लेकिन अपने इस नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि 2010 के आसपास इसकी गति धीमी होनी शुरू हो गई और यह पृथ्वी की सतह से धीमी रफ्तार में घूम रहा है। इस बारे में अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता प्रोफेसर जॉन विडेल ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि, जब मैंने पहली बार इस बदलाव को दर्शाने वाले सीस्मोग्राम देखे, तो मैं हैरान रह गया। लेकिन इसी पैटर्न का संकेत देने वाले दो दर्जन से अधिक अवलोकन मिलने के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि दशकों में पहली बार आंतरिक कोर धीमा हो गया है।

किन कारणों से हो रहा है यह बदलाव- शोध के मुताबिक आंतरिक कोर अब पृथ्वी की सतह की तुलना में धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, जैसे की यह पीछे की ओर जा रहा हो। ऐसा करीब 40 वर्षों में पहली बार हुआ है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बार-बार आने वाले भूकंपों और भूकम्पीय तरंगों का उपयोग किया है। यह भूकंप एक ही स्थान पर बार-बार आते हैं और समान सीस्मोग्राम बनाते हैं। अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 1991 से 2023 के बीच दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह के पास 121 बार आने वाले भूकंपों के भूकंपीय आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इसके साथ ही उन्होंने 1971 और 1974 के बीच सोवियत परमाणु परीक्षणों और आंतरिक कोर के अन्य अध्ययनों से दोहराए गए फ्रांसीसी और अमेरिकी परमाणु परीक्षणों के आंकड़ों का भी मदद ली है। विडेल ने इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए प्रेस से साझा की जानकारी में कहा है कि आंतरिक कोर की धीमी होती गति, उसके चारों और बाहरी कोर में घूमते तरल लोहे के मंथन की वजह से है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। इसके ऊपर चट्टानी मेंटल के घने क्षेत्रों से गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है। विडेल के मुताबिक कोर की धीमी होती गति के लिए उसके चारों ओर घूमते तरल लोहा की वजह से है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है। इसके साथ ही गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की भी इसमें भूमिका है। इसके प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए शोधकर्ताओं ने जानकारी दी है कि आंतरिक कोर की गति में परिवर्तन से दिन की अवधि पर मामूली प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन आम लोगों द्वारा इसे नोटिस करना बहुत कठिन है। भविष्य में वैज्ञानिक आंतरिक कोर का अधिक बारीकी से अध्ययन करना चाहते हैं ताकि यह समझा जा सके कि इसमें यह बदलाव क्यों आ रहे हैं। विडेल को लगता है कि आंतरिक कोर की हलचलें हमारी कल्पना से कहीं अधिक दिलचस्प हो सकती हैं। गौरतलब है कि इसी साल मार्च 2024 में जर्नल नेचर में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में सामने आया था कि ध्रुवों पर जमा बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण पृथ्वी की घूर्णन की रफ्तार धीमी हो रही है। इसकी वजह से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी वजह से हमे कुछ वर्षों के भीतर पहली बार लीप सेकंड को घटाने की आवश्यकता पड़ सकती है।

आगामी पशु गणना हेतु भारत सरकार द्वारा मोबाइल एप लॉन्च

भोपाल (एजेंसी)केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 21वीं पशुधन गणना की तैयारी के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीति बनाने और सशक्त करने के लिए कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और श्री जॉर्ज कुरियन भी मौजूद थे। कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री ने 21वीं पशुधन डेटा संग्रह के लिए विकसित मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए पशुधन क्षेत्र का महत्व बताया। उन्होंने पशुधन गणना की सावधानीपूर्वक योजना बनाने और उसे लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एकत्र किया गया डाटा, भविष्य की पहलों को आकार देने और क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य सितंबर-दिसंबर 2024 के दौरान निर्धारित आगामी पशुधन गणना के लिए एक समन्वित और कुशल दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। गणना के आंकड़े सतत विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय संकेतक ढांचे में योगदान देंगे, जिससे व्यापक राष्ट्रीय और वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के साथ तालमेल किया जा सकेगा।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव सुश्री अलका उपाध्याय ने अपने संबोधन में इस कार्यशाला के महत्व बताते हुए कहा कि यह विभाग सटीक और कुशल डेटा संग्रह के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने 21 वीं पशुधन गणना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया और कहा कि यह पशुपालन क्षेत्र की भविष्य की नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नई सरकार, नई उम्मीदें- कचरा डालने को हतोत्साहित करें, व्यवहार परिवर्तन में निवेश करें

भोपाल। केंद्र में गठबंधन की नई सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है। इस सरकार की नीतियां और उनका तय किया गया रास्ता हमारा भविष्य तय करेगा। इस नई सरकार से देश को आखिर किन वास्तविक मुद्दों पर ठोस काम की उम्मीद करनी चाहिए ? लेकिन ये उम्मीदें क्या होनी चाहिए, डाउन टू अर्थ अलग-अलग विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए लेखों की कड़ियों को प्रकाशित कर रहा है। अब तक आप पर्यावरणविद सुनीता नारायण के लेख (लेख के लिए क्लिक करें) के अलावा 2030 के जलवायु लक्ष्यों को ध्यान में रखकर होना चाहिए विकास , अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने में कहीं 57 साल न लग जाएं!

पिछले दशक में भारतीय शहरों ने कचरा प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाने वाले कार्यक्रम हैं- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), 2014 में शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम जिसका लक्ष्य खुले में शौच को खत्म करना और स्वच्छता प्रणाली को बेहतर बनाना है; और स्वच्छ सर्वेक्षण, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा इन विकास लक्ष्यों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक मूल्यांकन उपकरण। इन कार्यक्रमों ने कचरा प्रबंधन का फोकस सिर्फ %दिखावटी सफाई% से हटाकर %कचरे से धन% की ओर स्थानांतरित कर दिया है, फिर भी भारतीय शहर प्रदूषण के मामले में पीछे ही हैं। यह महत्वपूर्ण है कि नई सरकार कचरा प्रबंधन की कला और विज्ञान को फिर से सीखे।

कोई झूठा समाधान नहीं- पहली नजर में, कचरे से धन कमाना उन शहरों के लिए फायदे का सौदा लगता है जो कचरे के ढेर में डूबे हुए हैं। उदाहरण के लिए, नगरपालिका के ठोस कचरे में मौजूद जैव-अपघटनीय पदार्थों का उपचार बायोगैस या कम्पोस्ट बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद भी भारत में एक भी कचरे से ऊर्जा बनाने का संयंत्र ऐसा नहीं है जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरण के अनुकूल हो। इस विरोधाभास का एक कारण यह है कि शहर अभी भी मिश्रित कचरे को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अलग न किया गया कचरा अक्रिय और खतरनाक पदार्थों को समेटे हुए होता है और उसमें ऊष्मीय मान कम होता है, जो इन संयंत्रों को प्रदूषणकारी और अलाभकारी बना देता है।

स्रोत पर कचरे को अलग करने में सुधार के लिए सख्ती से नियम लागू कराना और व्यवहार परिवर्तन के उपाय करना उचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए कचरे को अलग-अलग एकत्र करना और ले जाना लैंडफिल टैक्स और जैव-अपघटनीय, ज्वलनशील कचरे को फेंकने पर रोक लगाकर कचरा डालने को कम करना इसी तरह, जब कचरे को अलग नहीं किया जाता है, तो प्लास्टिक, कागज और धातु जैसे रिसाइकल हो सकने वाले कचरे कार्बनिक कचरे से गंदे और दूषित हो जाते हैं। इससे इनकी बाजार में कम कीमत मिलती है। कचरे से धन प्राप्त करने के लिए, सरकार को इन उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।

व्यवहार परिवर्तन पर जोर- चूंकि कचरा प्रबंधन यूएलबी और नागरिकों के बीच साझा जिम्मेदारी है, इसलिए स्रोत पर कचरे को अलग करने और घर पर खाद बनाने को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार परिवर्तन में %निवेश% करने के लिए नीतिगत उपायों को लागू किया जाना चाहिए। इन उपायों से होने वाले लाभ को भुनाने के लिए किसी व्यवस्था की जरूरत है।

नगरपालिका के बाई-लॉज का कानूनी उपकरण के तौर पर इस्तेमाल- संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992, शहरी स्थानीय निकाय को बाई-लॉज के माध्यम से स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने और उन्हें लागू करने के लिए उपयोग करने का अधिकार देता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई), दिल्ली द्वारा 37 शहरों में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि कानून में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, उनमें से सभी शहर स्रोत पर कचरे को अलग करने को लागू करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि शहरों के पास कचरे के उपचार या प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है।

उपचार को प्राथमिकता मिले- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 2021 की नवीनतम रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि शहर 95 प्रतिशत कचरा इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें से केवल 50 प्रतिशत का ही उपचार किया जाता है। शेष कचरे को बिना उपचार या प्रसंस्करण के लैंडफिल में या अन्य जगहों पर फेंक दिया जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि जब तक कचरे को अलग-अलग एकत्र और ले जाया नहीं जाता, तब तक कचरे के आसपास एक व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बनाया जा सकता। सरकार को चुनौती से निपटने के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए-

रियायत समझौते को नया रूप दिया जाए- आधे शहरों में ठेकेदार कचरे के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन्हें स्थानीय शहरी निकायों (यूएलबी) से मिश्रित कचरे के संग्रह के आधार पर भुगतान मिलता है। अलग किए गए या उपचारित कचरे की मात्रा के अनुसार रियायतकर्ताओं को भुगतान करने के लिए सतत सार्वजनिक खरीद पर एक राष्ट्रीय नीति लागू की जानी चाहिए।

विकेंद्रीकरण महत्वपूर्ण है- मिश्रित कचरे को लैंडफिल तक ले जाने और जमा करने में कुल बजट का 40 से 60 प्रतिशत खर्च हो जाता है। स्रोत पर अलग किए गए कचरे के उपचार के लिए स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इससे परिवहन लागत में काफी कमी आएगी और लैंडफिल में जाने वाले कचरे को कम किया जा सकेगा। ओडिशा के 114 यूएलबी (स्थानीय शहरी निकाय) इस विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण को लागू कर रहे हैं।

कूड़े के बड़े उत्पादकों पर लगाम- अनुमान बताते हैं कि हाउसिंग सोसायटियों और उद्योगों जैसे थोक कचरा उत्पादक कुल पैदा होने वाले कचरे का 30 प्रतिशत पैदा करते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, उन्हें अपने परिसर में ही जैविक कचरे का प्रबंधन करना चाहिए। लेकिन सीएसई के अध्ययन में पाया गया है कि बड़े कूड़ा उत्पादक इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सीएसई का अनुमान है कि अगर इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाए, तो शहरों का कचरा प्रबंधन बोझ 40 प्रतिशत कम हो सकता है।

अनौपचारिक क्षेत्र को शामिल करें- कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए, पुणे नगर निगम ने 4,500 कूड़ा बीनने वालों के सहकारी समिति के साथ घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने के लिए एक समझौता किया है। निगम उन्हें वेतन नहीं देता है, लेकिन उन्हें घरों से कचरा इकट्ठा करने का शुल्क लेने और रिसाइकिल किए जा सकने वाले कचरे को बेचने की अनुमति देता है। इस तरीके से कचरे को अलग-अलग करने की गारंटी मिली है और इकट्ठा करने की लागत में 45 प्रतिशत की कमी आई है। पूरे भारत में ऐसे उपायों को अपनाया जाना चाहिए। कचरा प्रबंधन एक महंगा काम है। कचरा इकट्ठा करने और ले जाने का खर्च 1500 रुपये से 3000 रुपये प्रति टन तक आता है। पहाड़ी इलाकों में ये खर्च और भी ज्यादा होता है। इसलिए, कूड़ा खुले में फेंकने को हतोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं-

जीवन के लिए काफी उपयुक्त है पीलीभीत का वातावरण - मनीष

पीलीभीत। भारत विकास परिषद की टाइगर नगर शाखा की ओर से चलाए जा रहे पर्यावरण पखवाड़े का मंगलवार को गांधी स्टेडियम में समापन हो गया। पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि पीलीभीत का वातावरण जीवन के लिए काफी उपयुक्त है। भारत विकास परिषद की ओर से 10 जून से पर्यावरण पखवाड़ा शुरू किया गया था। समापन पर अतिथियों को पटका पहनाकर स्वागत किया गया। परिषद के वरिष्ठ सदस्य राजकीय इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य आरपी गंगवार ने सभी का स्वागत किया। शाखा अध्यक्ष सौरभ सक्सेना ने कहा कि पर्यावरण पखवाड़े के दौरान हुए कार्यक्रमों की जानकारी दी। पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने कहा की पीलीभीत का वातावरण जीवन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यहां के जंगल और जल स्रोत की हम सबको रक्षा करने की जरूरत है। आज जो भी पेड़ हम लगाएं उनको जीवित रखें। यही हम सब का उद्देश्य रहना चाहिए। परिषद के जिला प्रभारी डॉक्टर अनिल सक्सेना ने बताया कि भारत विकास परिषद राष्ट्र हित में समाज के लिए काम करती है। पर्यावरण संयोजक अनिल मेनी और विशिष्ट अतिथि क्रीड़ा अधिकारी राजकुमार ने भी विचार रखे। शाखा सचिव जगदीश सक्सेना ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में डॉक्टर विजय कुमार सिंह, मनोज मित्तल, नीमा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अश्वनि सचदेवा, रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष घनश्याम अग्रवालॉ, रवि अग्रवाल, गुड्डू भैया आदि मौजूद रहे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008